ved during the period 1990—92 are as follows:—

Year	(Rs. in Millions)
1990	52.40
1991	197.00
1992	4391.30

(b) The investment response as reflected in the approvals given during the years 1990—92 for foreign investments shows a significant increase. The figures for the years 1990, 1991 and 1992 are Rs. 1283.20, Rs. 5341 10 and Rs. 38875.40 millions respectively. No formal study has, however, been undertaken so far by the Government on foreign investments and NRI investments.

उत्तर प्रदेश के बड़े कृषकों को बैंकों से दिये गये ऋण

897. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने उत्तर प्रदेश की बड़ी-बड़ी नदियों के किनारों पर रहने वाले किसानों को पाइप लाइन बिछाने और बिजली की मोटरें लगाने के लिये 50 हजार से 3 लाख रुपये तक के ऋण दिये हैं ;

(ख) क्या सरकार इन किसानों के ऋणों को माफ करने का विचार रखती है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार इन पाइप लाइनों पर 50 प्रतिशत राज सहायता देने का विचार रखती है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) आंकड़ा सूचना प्रणाली में पूछे गये ढंग से सूचना एकत्र नहीं की जाती है। अलबत्ता, जून 1990–91 (नवीनतम उपलब्ध) के अन्त की स्थिति के अनुसार, लघु सिंचाई योजना के लिये उत्तर प्रदेश में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की बकाया राशि भी लगभग 3 लाख खातों में 225 करोड़ रुपये थी।

(ख) और (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऋणों को सपाट रूप से बट्टे खाते डालने के हक में नहीं हैं। तथापि, भारत सरकार और राज्य सरकारों ने किन्हीं वर्गों के पात्र उधारकर्ताओं को 10,000/– रुपये प्रति उधारकर्ता ऋण राहत प्रदान करने के लिये मई, 1990 में एक योजना तैयार की थी। यह योजना पहले ही 31 मार्च, 1991 को समाप्त हो गई है।

(घ) पाइप लाइन आदि बिछाने के लिये बताई गई सब्सिडी प्रदान करने संबंधी राज्य सरकार की किसी योजना की जानकारी नाबार्ड के पास नहीं है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुये प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

उत्तर प्रदेश को अनुदान राशि/ऋण राशि में कमी

898. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 और विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश को दी गई वार्षिक अनुदान राशि और लघु अवधि ऋण राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश को दी गई वार्षिक अनुदान राशि और लघु अवधि ऋण राशि में कमी हुई है

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) 1989–90 से 1992–93 के दौरान उत्तर प्रदेश को स्वीकृत/आबंटित वार्षिक अनुदान नीचे दिये गये अनुसार हैं :–

	(करोड़ रु० में)
1989–90(स्वीकृत)	564.80
1990–91(स्वीकृत)	1149.50
1991–92(स्वीकृत)	1351.74
1992–93(आबंटित)	1434.70

वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को कोई अल्पावधि ऋण स्वीकृत नहीं किये जाते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Allotment of land by A.D.D.A. to R.B.I. at Durgapur

899. SHRI ASHIS SEN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India has taken possession of a plot of land allotted by Asansol Durgapur Development Authority for opening of an office of Reserve Bank of India at Durgapur;

(b) if so, what is the date of possession; and

(c) by when the Reserve Bank of India is likely to open the projected office there?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) Reserve Bank of India have reported that they have acquired land on lease in the Steel township at Durgapur from the Steel Authority of India Limited and taken possession of the same in July, 1984.

(c) Reserve Bank of India do not have any plan for opening of office at Durgapur in the near future.

समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के द्वारा बैंकों में खोले गये खाते

900. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कमजोर वर्गों के लोगों तथा कारीगरों, ग्रामीण और लघु उद्योगों के श्रमिकों द्वारा बैंकों में खोले गये खातों की संख्या विगत दो वर्षों की तुलना में कम हो गई है और इन वर्गों के व्यक्तियों को दिये गये ऋणों की राशि में भी कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय बैंक इन वर्गों के लोगों की उपेक्षा कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन वर्गों के लोगों को अधिकतम सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसरण में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित सभी भारतीय बैंकों को अपने कुल ऋण का कम से कम 10% ऋण कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों सहित कमजोर वर्गों को देना अपेक्षित है। जून, 1990 और जून 1991 (अद्यतन उपलब्ध) को समाप्त वर्ष के दौरान कमजोर वर्गों